भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1332

दिनांक 09 **फरवरी**, 2023

गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास

1332. **श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आयात बिल को कम करने के लिए देश के गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास हेतु कोई दीर्घकालिक योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दीर्घकालिक योजना के कारण आयात बिल में कितनी राशि कम होने की संभावना है; और

(घ) आयात बिल को कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) आयात बिलों में कमी करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक दीर्घकालिक नीतिगत पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत छूटों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों से जुड़ी नीति, 2014
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016
iv. उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी नीति, 2016 और 2017
v. कोल बेड मिथेन के शीघ्र मौद्रीकरण संबंधी नीति, 2017
vi. नेशनल डेटा रिपोज़िटरी की स्थापना, 2017
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन, 2017
viii. हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन:-आकलन, 2017
ix. एनईएलपी-पूर्व तथा एनईएलपी ब्लॉकों, 2018 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए नीतिगत ढांचा

x. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीति, 2018

xi. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंम नियों को आबंटित कोयला खनन पट्टा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और दोहन संबंधी नीतिगत ढांचा, 2018

xii. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदाओं तथा नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा, 2018

xiii तेल और गैस का घरेलू अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंस नीति में सुधार, 2019

xiv. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020

xv. दिनांक 1 अक्तूबर, 2018 को किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल शुरू की गई थी जिसमें तेल और गैस विपणन कंम नियां (ओजीएमसीज) भावी उद्यमियों से संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) अधिप्रा त करने के लिए रु च की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं। दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 तक लगभग 225 टन प्रतिदिन की कुल उत्पादन क्षमता वाले 40 सीबीजी संयंत्रों को चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, सतत में भागीदारी कर रही तेल और गैस विपणन कंम नियों ने सीबीजी की अधिप्राि ति के लिए उद्यमियों को लगभग 3826 आशय पत्र जारी किए हैं। 97 खुदरा बिक्री केन्द्रों से सीबीजी की बिक्री शुरू कर दी गई है तथा सीबीजी-सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना के तहत नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के 12 भौगोलिक क्षेत्रों में सीबीजी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

xvi. 11ए बोली दौर के बाद पीएनजीआरबी ने पूरे देश में 630 जिलों में फैले हुए नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, जो 98 प्रतिशत आबादी और 88 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है, के विकास के लिए 295 भौगोलिक क्षेत्रों को प्राधिकृत किया है। दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार 102.03 लाख से अधिक पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन दे दिए गए हैं और पूरे देश में 4918 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा की वास्तविक बचत कच्चे तेल के मूल्यों और लागू विदेशी विनिमय (फोरैक्स) दरों आदि जैसे विभिन्न बाहरी घटकों पर निर्भर करती है। तथापि, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2021-22 (दिसंबर, 2021-नवंबर, 2022) के दौरान पेट्रोल में एथेनॉल के मि ण से अनुमान है कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में 22,500 करोड़ रुपए से अधिक की कमी हुई थी।

(घ) आयात बिल में कमी करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता (हाइड्रो, परमाणु, सौर पीवी, पवन, बायोमास आदि) से 500 जीडब्ल्यू संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, सरकार ने देश में जैव ईंधनों की उपलब्धता बढ़ाने और आयात निर्भरता कम करने, स्व छ ईंधन को प्रोत्साहित करने और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एथेनॉल मि ण, जैव डीजल मि ण और संपीड़ित जैव गैस के लिए विभिन्न पणधारकों को शामिल करते हुए पूरे देश में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक (सतत) के जरिए संपीड़ित जैव ऐथेनॉल, जैव डीजल और जैव सीएनजी जैसे वैकल्पिक स्व छ ईंधनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 शुरू की है। विद्युत मंत्रालय के अनुसार थर्मल, लार्ज हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा क्षमता में भी काफी वृद्धि की जा रही है।

****